

आयकर स्लैब : कोई बदलाव नहीं, मध्य वर्ग को फिर झटका

पूंजीगत व्यय : 35.4 फीसदी ज्यादा 7.5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

स्टार्टअप व एमएसएमई को राहत एक साल बढ़ाई

रियल एस्टेट



मधुबन बापूधाम स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना। संवाद

पीएम आवास योजना से पूरा होगा घर का सपना

माई सिटी रिपोर्टर

उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया बजट

गाजियाबाद। आम बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विकासकर्ताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। 80 लाख पीएम आवास के निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ बजट आवंटन के निर्णय को किफायती आवास मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम बताया। निर्णय से सेक्टर में सकारात्मक भावना आने के साथ मांग और आपूर्ति में बढ़ोतरी की बात कही। दूसरी ओर सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित रियल एस्टेट सेक्टर की विभिन्न मांगों को बजट में अनदेखा किए जाने से निराशा भी जताई। दूसरी ओर विकासकर्ताओं ने परिवहन के क्षेत्र में सुधार से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिलने की बात भी कही।



बजट रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित कई अन्य मांगें इस बार भी पूरी नहीं हुई हैं। वपुल गिरी, अध्यक्ष, क्रेडाई गाजियाबाद

बजट संतुलित, पर कई मांगें नहीं हुई पूरी



बजट संतुलित और समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। बजट में सभी के लिए किफायती आवास पर जोर दिया गया। मनोज गौड़, सीएमडी गौड़ ग्रुप व उपाध्यक्ष नार्थ, क्रेडाई



मांगों को किया अनदेखा, निराशा लगी हाथ

बजट में रियल एस्टेट की लंबे समय से चली आ रही मांगों को फिर अनदेखा किया गया है। अब पूरे सेक्टर के लिए उद्योग की स्थिति के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहे थे। मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान से रोजगार के अवसर निकलेंगे। - यश मिगलानी, एमडी, मिगसन ग्रुप



सेक्टर में बढ़ेगी मांग

पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी बजट किफायती आवास पर केंद्रित रहा। पीएम आवास के लिए बजट का आवंटन सराहनीय कदम है। निर्णय समग्र आवास उद्योग के लिए बूस्टर हो सकता है। निर्णय सेक्टर में सकारात्मक भावना लाने के साथ मांग और आपूर्ति में वृद्धि करेगा। - धीरज जैन, डायरेक्टर, महागुन ग्रुप